SHRI RAJESH PILOT: Sir, he is very right. This is also one of the factors. Normally we have "collectors" to collect oil and other things which are discharged while a ship is waiting for berthing. With all these factors in mind we are coming out with a comprehensive plan for each port. Some measures have already been taken in some ports, and in some they are in the process. It is a continuity; it cannot be just one day's work.

MR. CHAIRMAN: They want that there should not be a long wait.

SHRI A. G. KULKARNI: Is it a comprehensive plan for Bombay Port alone or for other ports also?

SHRI RAJESH PILOT: For all ports. Each individual port will have a separate plan. If the honourable Member is keen about Bombay Port, I can tell him what comprehensive plan we have for the Bombay Port.

SHRI KAMAL MORARKA: Sir, about the Bombay Port Trust, the honourable Minister has said that the powers of its Chairman have been extended and purchases up to Rs. 4 crores can be handled locally. I want to know whether these purchases will also cover, apart from pollution control equipment, certain other things which have been pending for a long time—about which I have written to the Minister also—like the containerization programme and other things which are pending at the Ministry level. Does this decentralization of power include a host of other things which can expedite decision-making in Bombay or is it limited to purchase of certain types of equipment only?

SHRI RAJESH PILOT: I think I could not make myself clear to the honourable Member. I said that the financial powers of the Chairman of Bombay Port Trust have been enhanced so that he could take decision and action up to Rs. 4 crores. That includes everything, even the projects which are in the Port. The Port Trust can take decisions up to Rs. 4 crores. So, that will cover what all you have meant.

Operation Blackboard for Prim Schools

*282. SHRI LAL K. ADVANI:
SHRI ASHWANI KUMAR:†

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) when was the Operation Blackboard for primary schools approved and what facilities were proposed to be included in the scheme;

(b) what is the State-wise number of such schools which have been provided with these facilities so far and what is the feed back about the continuation and utilisation of the facilities; and

(c) what targets have been fixed for the year 1988-89, State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) The scheme of Operation Blackboard, which was finalised in May 1987, envisages provision, in a phased manner for all primary schools, which had been established by 30-9-1986, of the following facilities:

(i) two reasonably large rooms usable in all weather;

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Ashwani Kumar.

(ii) an additional teacher, as far as possible one of them a woman, in every single-teacher school;

(iii) essential teaching and learning material as per Annexure-I attached. (*See* below).

(b) The State-wise number of schools which have been covered under the scheme of Operation Blackboard in 1987-88 is given in the attached Annexure-II (*See* below). Most of the sanctions under Operation Blackboard were issued in the last quarter of 1987-88, and specific reports regarding implementation in the States/UTs have not yet been received.

(c) The target envisaged in the scheme of Operation Blackboard for 1988-89 was coverage of 30 per cent blocks/municipal areas in all States/UTs. However, owing to financial constraints the targets for the current financial year have had to be reduced to 28 per cent.

Annexure-I

Essential facilities at the primary stage

I. *Teachers' equipment*
  - (i) Syllabus
  - (ii) Text books
  - (iii) Teachers' Guides

II. *Classroom teaching materials*
  - (i) Maps — District, State, Country, World
  - (ii) Plastic Globe
  - (iii) Educational Charts (Health) Social Studies, Language)

III. *Play materials and toys*
  - (i) Wisdom blocks (construction of different designs, patterns, objects, etc.)
  - (ii) Bird and Animal puzzle (Jigsaw puzzle)
  - (iii) Toys (Dolls, Human figures, Animals, Science toys)

IV. *Games equipment*
  - (i) Skipping Rope
  - (ii) Balls — Football, Valleyball, Rubber balls
  - (iii) Air pump
  - (iv) Ring
  - (v) Swing rope with tyre

V. Primary Science Kit (of NCERT)

VI. Mini Tool Kit (of NCERT)

Mathematics Kit

Books for Library
  - (i) Reference Books—Dictionaries, Encyclopaedia
  - (ii) Children's Books (at least 200) (NBT, Children's Book Trust, Nehru Bal Pustakalaya & other)

(iii) Magazine, journals and news papers for teachers and children (one news-paper, one magazine and one professional journal.)

IX. School Bell

X. *Musical Instruments*

Dholak or Tabla

Harmonium

Manjira

XI. *Contingency money with Teacher*

Recurring

(i) Mats and furniture for students and teachers (one chair & one table for one teacher + 2 large boxes)

For teachers

Mats

Boxes

XII. Blackboard

Pin-up Board (canvas)

XIII. Chalk and Duster

XIV. Water facility (pictures, glasses & ladle)

XV. Tresh Can

Annexure-II

Number of Schools covered during 1987-88 under Operation Blackboard

Sl. No.	Name of the State/U.T.	Number of Schools
1	Andhra Pradesh	6352
2	Assam	7014
3	Bihar	13270
4	Gujarat	4769
5	Haryana	959
6	Himachal Pradesh	1984
7	Jammu & Kashmir	1320
8	Karnataka	2473
9	Kerala	1467
10	Madhya Pradesh	13926
11	Maharashtra	6723
12	Manipur	541
13	Meghalaya	766
14	Nagaland	311
15	Orissa	7377
16	Punjab	4737
17	Rajasthan	12187
18	Sikkim	509
19	Tamil Nadu	5995
20	Tripura	421
21	Uttar Pradesh	18924
22	Arunachal Pradesh	353
23	Dadra & Nagar Haveli	17
24	Delhi	668
25	Goa	169
26	Lakshadweep	19
27	Mizoram	166
	TOTAL :	1,13,417

श्री अश्विनी कुमार : माननीय सभापति जी, मंत्री जी ने जवाब दिया है और बहुत लम्बी चौड़ी फहरिस्त भी दी है इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। परन्तु इन्होंने जितनी चीजें लिखी हैं क्या यह चीजें प्राइमरी स्कूलों में जो आप्रेशन ब्लैक बोर्ड योजना है, उपलब्ध हैं। यह मैंने प्रश्न पूछा है। मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार में 13270 स्कूल हैं इनका सर्वे किया गया जिसकी रिपोर्ट अखबार में छपी है। सभापति महोदय, इसमें ऐसे आंकड़े हैं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके अनुसार चाक और डस्टर 13270 स्कूलों में से मात्र 7 स्कूलों में हैं। ब्लैक बोर्ड आपरेशन जो कहा जा रहा है यह ढाई हजार स्कूलों में है। जो घंटी बजनी चाहिए जिसके बाद स्कूल में बच्चे आते हैं यह केवल 3770 स्कूलों में है, दो कमरे के स्कूल होने चाहिएं ऐसा इसमें बताया गया है। उस जानकारी के अनुसार केवल 2440 हैं जिसमें एक पक्का कमरा है और 3050 हैं जिसमें दो कमरे हैं तथा 835 ऐसे हैं जिसमें दो से ज्यादा हैं। टायलेट और शेड्स के बारे में बताया गया है। 13270 स्कूलों में से 144 स्कूल ऐसे हैं जिनमें टायलेट्स की व्यवस्था है। केवल तीन हजार...

श्री सभापति : आप क्वेश्चन पूछ लीजिए।

श्री अश्विनी कुमार : मैं सिर्फ डिटेल्स बता रहा हूं कि इन्होंने जो तीन पन्ने का स्टेटमेंट दिया है...

श्री सभापति : वह उनको दे दीजिएगा, वे ठीक कर देंगे। Have you provided these facilities? When are you going to provide them?

श्री अश्विनी कुमार : मेरा इतना ही प्रश्न है कि आपने जो कुछ प्रोवाइड करने की कल्पना की है, योजना बनायी है और अभी तक जो इसमें किया है यह कब तक पूरा करेंगे, इसको पूरा करने में कितना खर्च लगेगा और वह सारा खर्च केन्द्र सरकार स्वयं करेगी या उसमें से कुछ बिहार सरकार पर छोड़ा जा रहा है ?

श्री एल० पी० साही : जहां तक मकान का खर्चा है उसमें एन०आर०ई०पी० और आर०एल०ई०जी०पी० के अंदर फर्स्ट चार्ज प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग का होगा ऐसा निदेश सभी राज्य सरकारों को सेंट्रल कैबिनेट और प्लानिंग कमीशन की स्वीकृति के बाद भेज दिया गया है। जहां तक उसमें रेशियो का सवाल होता है कि एन०आर०ई०पी० में कितना लेबर कम्पोनेंट होगा और कितना मैटीरियल कम्पोनेंट होगा, इसके बारे में कहा गया है कि यह 50-50 का होगा ताकि मकान खड़ा हो सके। इससे अधिक मैटीरियल कम्पोनेंट लगाने की जरूरत है तो वह राज्य सरकार की जवाबदेही होगी। जहां तक आपरेशन ब्लैक बोर्ड में नक्शे, ग्लोब, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, खिलौने...

श्री सभापति : डस्टर।

श्री एल० पी० साही : डस्टर भी.. (**व्यवधान**) और इसके अलावा पढ़ाई, जितने साधन देने का सावाल है जिनकी फहरिस्त इसमें लगी हुई है उसके लिए पूरा खर्च भारत सरकार ने वहन करने का निश्चय किया है और जो 1987-88 में 20 प्रतिशत प्रखण्डों के अंदर यह काम चालू होना था इसके लिए स्टेट लेविल पर एक स्टेट लेविल इम्पावर्ड कमेटी बनायी गयी थी... (**व्यवधान**) उसकी मीटिंग भी हुई है उसकी मीटिंग कराकर वहां के प्रोजेक्ट्स मंगाकर हम लोगों ने स्वीकृति दी है लेकिन पहले वर्ष में प्रोजेक्ट आने में देरी हुई है और ज्यादातर यह स्वीकृति जो हुई है, यहां से पैसे की मिली है वह मार्च 1988 में मिली है। तो मार्च महीने में हम लोगों ने वह पैसा राज्य सरकारों को 1987-88 का दिया है। ज्यादातर उनकी मीटिंग्स भी फरवरी और मार्च में हुई है जिसके बाद हमारे यहां वे स्वीकृति के लिए आए। इसलिए सारे देश के जिन राज्यों ने इसको लिया है वेस्ट बंगाल को छोड़कर, उनके 20 प्रतिशत ब्लाक्स के लिए हम पैसे दे चुके हैं... (**व्यवधान**)

श्री सभापति : जो देना चाहिए था उसका 20 प्रतिशत दिया है और अभी 80 प्रतिशत बाकी है ?

श्री एल० पी० साही : 80 प्रतिशत में इस वर्ष के लिए पहले से अंदाज था, हम लोगों ने योजना बनायी थी कि 30 परसेंट ब्लाक्स को दे देंगे लेकिन सूखे की वजह से जो फाइनेंशियल कन्सट्रेंट्स हुए उसकी वजह से हम यह 30 परसेंट शायद नहीं दे सकेंगे।

श्री सभापति : अब तो पानी बरस गया है।

श्री एल० पी० साही : पानी बरसने के बाद पैसा बढ़ेगा तो फिर बढ़ा देंगे।

श्री सभापति : अब 30 परसेंट की वजह कितना करने वाले हो। आपका प्लान 30 परसेंट का था... (**व्यवधान**) अब 20 परसेंट देंगे... (**व्यवधान**) अब यह पूछ रहे हैं कि हुआ क्या ? वहां उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ ? यह बिहार का सवाल है।

श्री एल० पी० साही : इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो पैसा हमने मार्च में दिया है और सब से प्रोफार्मा भेजकर रिपोर्ट मांगी है लेकिन अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई है।

श्री सभापति : जल्दी करवाइये और सूचित कर दीजिए।

श्री एल० पी० साही : इसलिए हम तकाजा कर रहे हैं कि रिपोर्ट जल्दी दें और

जब तक वे पिछले साल की रिपोर्ट नहीं देंगे तब तक अगले साल के लिए हम पैसा उपलब्ध कराने वाले नही हैं यह भी उनको कह दिया है।

श्री सभापति : उससे प्राब्लम तो हल नहीं होगी। चलिए आप सवाल कीजिए।

श्री अश्विनी कुमार : सभापति महोदय, बिहार में मार्च लूट बड़ी प्रसिद्ध है। वहां एक लूट होती है कि 31 मार्च के बिल 15 अप्रैल तक बनते रहते हैं और बिना काम किये बिना बहुत सारा पैसा निकल जाता है। इस बार मंत्री महोदय ने उसी मार्च लूट के अंदर और पैसा डाल दिया है।

श्री सभापति : आपके प्रदेश के लोग लूट ले जाते है... **(व्यवधान)**

श्री अश्विनी कुमार : मंत्री जी भी हमारे प्रदेश के है इसलिए मार्च लूट कर दिया ... **(व्यवधान)** जब यह बात आप कह रहे है मैं नहीं कह रहा हूं। यह सभापति महोदय कह रहे हैं, मैं नही कह रहा हूं। सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है... **(व्यवधान)** कि ये सारी सुविधाएं केन्द्रीय सरकार जब तक प्रदान नहीं कर सकती तब तक यह होगा कि जो हमने योजना बनाई है, यह केन्द्रीय सरकार को आज से नहीं बहुत पहले से योजना है कि 14 साल तक के सब बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देंगे, यह योजना सफल नहीं होगी और स्कूलों में से बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे ड्राप आउट हो जायेंगे। निकलने के जो कारण हैं उसमें यह भी है कि बच्चे को घर में काम होता है, उसके पास पर्याप्त कपड़े पहनने के लिए नही हैं। ये सारे जितने फैक्टर्स आपके सामने रखे गये हैं मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या कोई इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि स्कूल का वातावरण आकर्षक हो, जो टीचर्स है वे घर बैठकर वेतन न लें, वहां आये और जो स्कूल हो उसको वास्तविक स्कूल बनाने की आवश्यकता की पूर्ति हो ताकि आज जो पहली से पांचवी क्लास तक ड्राप आउट 65 प्रतिशत है वह कम हो। अत: इन सबके लिए क्या कल्पना है, क्या योजना है, और इसको कैसे पूरा करेंगे ?

श्री एल० पी० साही : सभापति महोदय, सवाल तो आपरेशन ब्लैक बो का है ...

श्री सभापति : यह भी उसी का पार्ट है और आपके यहा जो प्लान है उसमें सब लिखा है ... **(व्यवधान)** पाइंट यह है कि सीधे सीधे आप सुपरवाइज कीजिए, देखिए कि जो आप कह रहे है वह वहां हो रहा है ? उसके नतीजे में विद्यार्थी आ रहे है और इसके लिए आप कुछ स्टेप्स उठाएंगे ?

श्री एल० पी० साही : इन स्कूलों को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए जहा एक शिक्षक था उन सब में दूसरा शिक्षक केन्द्रीय सरकार के खर्च पर इस प्लान पीरियड में हम लोगों ने दिया है और दूसरे शिक्षक बहाल भी हुए हैं। उन्होंने बिहार की बात कही है। मै वहां दो जिलों में गया था। वहां ऐसे हजारों शिक्षको को जो ट्रेनिंग पाकर बैठ थे अभी मार्च अप्रेल महीने में एपाइंटमेंट लेटर्स मिले है।

श्री सभापति : आप कोशिश कीजिए जितनी जगह वहां हो सके हो जाये।

श्री० एल० पी० साही : जितनी जगहें है उनको भरनेकी पूरी कोशिश हो रही है और जहां तक माननीय सदस्य का अंदेशा हैं कि यह खर्च न हो इसी लिए हमने प्रोफार्मा बनाकर सब राज्य सरकारों से मांगा है कि किसमें कितना खर्च हुआ है।

श्री सभापति : याद कराते रहिएगा।

श्री एल० पी० साही : अपने मंत्रालय में दूसरी मीटिंग करने के लिए सब जगह रिप्रेजेंटेटिव्ज भेज रहे हैं जो स्टेट लेविल इम्पावर्ड कमेटी की बैठक के समय जायेंगे, वहां देखेंगे कि क्या हुआ ?

श्री अश्विनी कुमार : ड्राप आउट्स को कम करने के लिए आपने कुछ नहीं बताया।

श्री एल० पी० साही : ड्राप आउट को कम करने के लिए नान फारमल की तरफ ले जा रहे हैं और स्कूल्स को आकर्षक

बनाएंगे तो ड्राप आउट कम होगा, इसकी भी कोशिश हा रही है ।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: My quetion relates to the financial allocation for the Operation Blackboard. The financial allocation made for the year was Rs. 1,463 crores. Because of drought condition, it is now being reduced to Rs. 800 crores. My question to the hon. Minister is if he takes at least one lakh schools that are proposed to be covered now and takes an expenditure on an average of Rs. 1 lakh for each school to be covered by the Operation Blackboard, he will get about Rs. 1,000 crores that he requires. In view of this is there any proposal by the Department of Education to link up the needs of Operation Blackboard such as the school buildings and other equipment along with the work being done by other educational institutions, as for instance low-cost housing and inexpensive equipment? To acquire these low-cost housing expertise and inexpensive equipment is there any proposal by the Department of Education to link up with other national institutions in order to reduce the financial constraint for Operation Blackboard?

Part (b) of my question relates to Tamil Nadu. I understand according to Operation Blackboard, there are three components. One component of the school building has to be funded by the State Government and the other components like salaries of the teachers and equipment are funded by the Central Government. As far as Tamil Nadu is concerned 5995 schools have been covered during 1987-88 under Operation Blackboard. May I know from the Minister whether the Government of Tamil Nadu have funded for school buildings for all these schools? Is there any other component that are to be funded by the Tamil Nadu Government which is the reason we have not been able to cover more schools in Tamil Nadu?

SHRI L. P. SHAHI: Sir, as the position stands, we tape an assurance from the State Government before sanctioning Operation lackboard. For school building they will provide from their own funds. The Tamil Nadu Government is one Government which has again sent its proposal for this year 1988-89. I think that is one State which has sent its proposal. The Tamil Nadu Government is in a position to implement the requirements of the buildings.

MR. CHAIRMAN: Are you trying for the whole country the new techniques for low cost housing in this context in order to reduce expenditure?

SHRI L. P. SHAHI: In this connection, Sir, we had a round of discussions with CBRI, Design Institute who are connected with the construction.

MR. CHAIRMAN: You are talking all these steps.

SHRI L. P. SHAHI: Yes, Sir.

PROF. C. LAKSHMANNA: Sir, the Minister while giving a reply he has said that the number of schools covered during 1987-88 under Operation Blackboard were 1,13,417 for the country and 6,352 for Andhra Pradesh. While replying to a supplementary, he has also stated that money was released in the month of March. May I know from the Minister when these 1,13,417 schools were covered? If the money was released in the month of March what was the month in which all these schools were covered? For the purchase of equipment, construction of buildings, etc., which has been given in the answer, takees some time. May I know from the Minister, when did he start? When did he finish? This is part (a) of my supplementary.

Part (b) is, may I know from the Minister whether 1,13,417 schools which have been covered are those schools where the facilities do not exist and the facilities have to be provided or are these schools where facilities already existed that have been

covered only under the programme? Ultimately, the entire country has to be covered under it.

Part (c) is...

MR. CHAIRMAN: The whole thing is augmenting. That is what it comes to...

PROF. C. LAKSHMANNA: The Minister has given a chart of essential facilities provided at the primary stage. But unfortunately the information which has been given in the Appendix cannot be read by anybody. The Ministry should take proper care to provide legible copies. This is the state of affairs in all the Ministries. Under syllabus item there is nothing leigible, no figure is legible. Likewise, textbooks and so on and so forth.

MR. CHAIRMAN: Is it not legible?

PROF. C. LAKSHMANNA: Absolutely not legible.

MR. CHAIRMAN: They are sent by the Ministry. Mr. Minister kindly see that next time it does not happen.

...(*Interruptions*)...

PROF. C. LAKSHMANNA: I think Jayanthi is always lucky. Twice she got a copy which is having all the information. But nonetheless...

MR. CHAIRMAN: Let us move on. I have told them that next time it should be legible. That is all.

PROF. C. LAKSHMANNA: Nonetheless under each of these items which have been listed in the proforma, there has been shortage of items which have been supplied during this year 1987-88. If so, what are the details under each of those items which have been supplied as a result of which 1,13,417 schools were covered during the last year?

MR. CHAIRMAN: We have to cover other people also. They will say that their questions have not come up.

PROF. C. LAKSHMANNA: Even this 1,13,000, again this year, that means 1988-89, will you see that the money is released not in the month of March and then wait for another three or four months to be covered—I do not know when it was covered exactly—instead of that, will you ensure that money is released to the different State Governments as per your own estimate of 20 per cent much before so that this programme is not becoming a programme of ad hocism and tokenism but reality?

SHRI L. P. SHAHI: Sir, as I have earlier stated, I did not mean to mince matters. Most of the meetings of the State level Empowered Committees itself were held in February and March. Therefore, the funds were released by the Government of India only in the month of March. So far as this year is concerned, we are trying from now on to hold the meetings of the State level empowered Committee, get their project reports earlier so that we could release the funds earlier. So far as supply of the items is concerned, we do not purchase and supply the items. We only give them money, give them a list that these are the syllabi which is prescribed by the NCERT or this is available there. It is for the State Governments to purchase that. We do not make the purchases.

SHRI KAMALENDU BHATTACHARJEE: Mr. Chairman, Sir, the scheme Operation Blackboard envisages provision, in a phased manner, of a very impressive list of facilities. So far as provision of these two reasonably large rooms usable in all weather is concerned, my State, Assam is a flood-prone and storm-prone area. Every time, these houses are totally demolished wasted away. what happens, Sir, is that it really becomes a large room usable in all whethers because there is no room at all. It

becomes **totally** something like open space. So, I would like to know from the hon. Minister wheher the Central Government is going to make any special provision for re-funding construction *of those buildings because* every year, these are washed away. There are floods and a number of schools, which have been by Operation Blackboard, this time also, the same thing happened to those schools. I want to know from the Minister, is *there any provision for helping* re-funding of those construction of the buildings.

SHRI L. P. SHAHI: Sir, as is well known to most of the hon. Members here, after the floods, a team is constituted by the Central Government which goes and assesses the amount of flood damage, whether it is in regard to roads, projects, school buildings or crops destruction. So, that is done by a separate Ministry of the Government of India. They assess the damage. (*Interruptions*)... As far as Operation Blackboard is concerned, under the Human Resource Development Ministry they give some amount for meeting the damages caused by floods. (*Interruption*).

SHRI KAMALENDU BHATTACHARJEE: But the amount is very meagre.

SHRI L. P. SHAHI: So far as buildings in flood prone areas is concerned, we have seen some buildings in certain areas whose plinth is raised to 5 feet, 6 feet or 7 feet high so that even if the flood comes, the building *is not disturbed* or damaged. There are some buildings in certain areas but that is for the State Government to consider which area **gets how** much ... (*Interruptions*) ...

MR. CHAIRMAN: Will you get in touch with the Housing Ministry and see what type of houses can be built?

SHRI KAMALENDU BHATTACHARJEE: It is a regular phenomenon. Every year, it happens so, Sir.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : सभापति महोदय माननीय मंत्रीजी ने बताया कि 1,13,417 स्कूल आपरेशन ब्लैक बोर्ड में सम्मिलित किए गए है। मैं जानना चाहूंगा कि लक्ष्य क्या था और 1,13,417 स्कूल जो स्थापित हुए हैं और जिस प्रकार की सामग्री सप्लायी करने की उन्होंने जो एक लंबी सूची दी है, इन कितने स्कूलों में वे अभी तक सामग्री सप्लायी कर चुके हैं ? जो एक अतिरिक्त महिला टीचर प्रोवाइड की जानी थी वहा वह कितने स्कूलों में महिला शिक्षक प्रोवाइड कर चुके है? साथ ही, मान्यवर, जो संगीत के साज सप्लायी करने की बात थी जैसे—ढोलक, मजीरा, हर्मोनियम, तो क्या कोई प्रशिक्षित टीचर इस प्रकार का है जो इन बच्चों को संगीत के साज बजाना सिखाएगा ?

श्री एल०पी० साही : जो एक लाख 13 हजार स्कूल की संख्य 20 परसेंट ब्लाक पर आई है हो सकता है कि दूसरे वर्ष 20 परसेंट ब्लाक में यह संख्या 2–4 घट जाए या बढ़ जाए। यह इस पर निर्भर करता है कि कौन कौन से ब्लाक चुने गए, उन ब्लाकों की क्या आबादी है, उनमें कितने स्कूल हैं यह तो ब्लाक के सलैक्शन पर निर्भर करेगा। वह संख्या थोड़ी घट-बढ़ सकती है।

श्री सभापति : आप 20 परसेंट दे रहे हैं और यह देखना है कि वह ठीक से हो रहा है, शिक्षक वहा पर एप्वाइंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : देखिए मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि कितने स्कूलों में सामग्री प्रोवाइड कर चुके हैं ?

श्री सभापति : सुनिए, आप मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश राज्य शासन में। आपको पता है कि केन्द्रीय शासन जो है वह प्राइमरी शिक्षक एप्वाइंट नहीं करता, वह पैसा दे सकता है, पैसा इन्होंने दिया है। यह तो मंत्री रह चुके हैं खुद, यह सब जानते हैं लेकिन अब पूछना है इसलिए पूछ रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : जो संगीत सज्जा की है इन्होंने इसके लिए कौन ट्रेनिंग देगा, कौन सिखाएगा, या बेकार पड़ा रहेगा ?

श्री सभापति : आप जरा यह बता दीजिए कि कौन-कौन सिखाते हैं स्टेट्स में क्योंकि किसी स्टेट में एक साज पसंद करते हैं, किसी में दूसरा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : देखिए साहब, क्या प्रश्न था और क्या उत्तर दे रहे हैं।

श्री सभापति : आप एक बात समझ लें कि पैसा दे रहे हैं । कहां पर ढोलक हो, कहां पर तबला हो कहां पर सारंगी हो, कहां क्या हो, यह तो राज्य शासन जो है वह करेगा ।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: This is not Operation Black-board. This is Operation Black-out.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर, जब हारमोनियम को बजाने वाला नहीं है तो फिर बच्चों को सिखाएगा कौन ?

श्रीमती सूर्यकांता जयवंत राव पाटील : मान्यवर, मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि देश में शिक्षा की स्थिति तो जो है, सदन में चर्चा हो रही है, उससे प्रकट हो रही है कि देश में शिक्षा की क्या स्थिति है । आपने एक करोड़ तेरह हजार चार सौ सत्रह जो नए स्कूल अतिरिक्त बनाने की सोची है, राज्य शासन को पैसा तो आपने आवंटित कर दिया मार्च में । जैसा हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि मार्च में जो पैसा दिया जाता है उसका विनियोग क्या होता है यह माननीय सदस्य भी जानते हैं, मंत्री जी भी जानते हैं । आइन्दा आप इसे मार्च से पहले देने की बात कर रहे है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन यह जो 1, 13, 417 अतिरिक्त स्कूल आप खोल रहे हैं इसके लिए जो अतिरिक्त शिक्षक चाहिएं, शिक्षिकाएं चाहिएं इसके लिए प्रावधान कुछ किया है और वह किया है तो कब किया है और नहीं किया है तो अब करना चाहते हैं ? मेरे प्रश्न क "बी" पार्ट है सर, कि यह जो पैसा आप देते हैं जिसके तहत आपने राज्य सरकार को कहा हैं कि वह एन०आर०ई०पी०, आर० एल०ई०जी० पी० द्वारा भवन निर्माण करे, क्या केन्द्र सरकार ने कभी यह देखा है कि राज्य सरकार के अंदर चलने वाले स्कूलों की स्थिति क्या है और वहां भवन निर्मिती हुई है या नहीं हुई है और आपने जो निधि दी है उसका उपयोग किस तरह राज्य सरकारें कर रही हैं, क्या इस बारे में केन्द्र सरकार को कुछ सूचना है ?

श्री एल० पी० साही : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं इस बात को साफ करना चाहता हूं कि एक लाख तेरह हजार नए स्कूल खोलने की बात नहीं है लेकिन इन 1,13,417 नए स्कूलों में 30,550 शिक्षक देने की जरूर बात है । जहां पर एक लाख तेरह हजार में से 30,550 ऐसे स्कूल थे जिनमें एक ही शिक्षक थे उनमें दूसरा शिक्षक देने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार को 58 करोड़ 66 लाख रुपया दिया है । उसी तरह टीचिंग ट्रेनिंग इक्यूपमेंट के लिए भी 41 करोड़ 58 लाख रुपया सभी राज्य सरकारों को, जिसकी जैसी जरूरत थी, बांट दिया गया है ।

श्रीमती सूर्यकांता जयवंतराव पाटील : मेरा प्रश्न यह है कि सिर्फ पैसा देना ही केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है या... (**व्यवधान**)... मान्यवर, मेरे सवाल का यह उत्तर नहीं है । पैसा देने के बाद उस पैसे का उपयोग राज्य सरकार किस तरह से करती है इस बात का उत्तर दीजिए ?

SHRI ALADI ARUNA **alias** V. ARUNACHALAM: Sir the object of the "Operation Blackboard" is to ensure

minimum . . . (*Interruptions*) ... essential facilities to the primary schools. According to the latest figures, the number of single-teacher schools in the country is 1,61,646 and the reduction within five years is 3,285. I would like to know from the honourable Minister how many teachers have been sanctioned to increase the strength of the single-teacher schools. Another more alarming fact, Sir, is that about 1,90,000 habitations are without any school facilities at all. I would like to know from the honourable Minister what steps have been taken to open new schools in those areas where no school facilities are available.

SHRI L. P. SHAHI: Sir under "Operation Blackboard", as I have already stated, there is a scheme to augment the existing schools and that is based on the survey conducted in 1978 has been mentioned by some of the honourable Members. So we are providing teachers to such schools by way of augmentation. We are also supplying teaching aids and other facilities to improve the standard of teaching. So far as coverage is concerned this is not covered under the "Operation Blackboard" scheme. The new thing is not covered under this scheme which is meant for augmenting the existing schools, for making them better, for providing them with teaching aids, buildings, etc.

SHRI ALADI ARUNA alias V. ARUNACHALAM: Sir, in the "Programme of Action" it has been clearly stated that additional teachers should be provided. It has been early stated in this document and it is for single-teacher schools. Sir, he has not answered my question.

SHRI L. P. SHAHI: Sir, the "Programme of Action" includes many things and... (Interruptions)

SHRI ALADI ARUNA alias V. ARUNACHALAM: How many new teachers have you provided so far? You have not answered this question.

SHRI L. P. SHAHI: I have just now said that we have provided during this year 30,550 new teachers. I have stated this earlier.

MR. CHAIRMAN: All right. Question No. 283.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, I am on a point of order... (Interruptions)....

MR. CHAIRMAN: Question No. 283. Mrs. Veena Verma. Not here. Shri Kapil Verma. Not here. Next Question ....(Interruptions) ....

*283. The questions (Shrimati Veena Verma and Shri Kapil Verma) were absent. For answer vide col. 34-35 infra——

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, I have a point of order to make ....(Interruptions)...This is not proper, Sir. Members give notice of questions and are not present in the House ....(Interruptions).. This is not proper.... (Interruptions)... .Public money is involved in this ....(Interruptions)....

MR. CHAIRMAN: Question No. 284 (Interruptions)..

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, she was seen in the Lobby....(Interruptions).... Sir, she was in the Lobby some time back.... (Interruptions).

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, kindly ask the Marshal to tell her to come ..(Interruptions).. This is waste of public money.... .. (Interruptions)..

SHRI DIPEN GHOSH: It is for avoiding the question ...(Interruptions)..

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I think they were asked to stay way ....(Interruptions)...

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Sir, my information is that she has been asked by her party to stay away ...(Interruptions)...

SHRI ALADI ARUNA alias V. ARUNACHALAM: Sir, she is sitting here in the Lobby... (Interruptions)

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, she is in the Lobby. Kindly ask the Marshal to call her here........ (Interuptions)....

SHRI V. GOPALSAMY: Sir, they have been taken away by a special aircraft....(Interruptions) ....

MR. CHAIRMAN: I request Members not to raise irrelevant things. I have no right to confine Members, belonging to this side or that side. After coming in the House they are free to move out. I have no right. (Interruptions)

AN HON. MEMBER: *I have given* you the information. She is.... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You can give it afterwards. Don't waste the time of the House.

SHRI DIPEN GHOSH: If it were a wilful act, I would not have objeced. But since she was made to leave the House.. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: According to me, it is my privilege to maintain discipline. And my ruling is that the question now raised is irrelevant. Kindly do not raise it. The Chair has no power to confine any Member within the precincts of the House. Please..(Interruptions) Question No. 284 Mr. Malaviya.

वाराणसी रामनगर-मुगलसराय को जोड़ने वाले गंगा के पुल का निर्माण

*284. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में वाराणसी रामनगर-मुगलसराय को जोडने के लिए गंगा नदी पर पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां ।

(ख) वाराणसी, रामनगर और मुगल सराय के बाहर से 36 कि०मी० लम्बी सड़क के साथ गंगा नदी पर एक पुल बनाने के लिए 49.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक परियोजना संस्वीकृत की गई है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : सभापति महोदय, बनारस के आस-पास की जनता की यह मांग करीब-करीब 50 वर्षों से चली आ रही है और इससे 15 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से कम होगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि वाराणसी, रामनगर और मुगलसराय को जोड़ने के लिए जो पुल बनाने की 50 करोड़ की योजना थी, इस पुल का निर्माण कार्य कब शुरू होगा और कितने दिनों में पूरा होगा और कब तक यह पुल आवागमन के लिए खुलने की आशा है ?

श्री राजेश पायलट : चेयरमैन साहब इस पुल की फाइनल रिपोर्ट 26 जुलाई, 1988 को स्टेट गवर्नमेंट के पास वेटिंग के लिए गई है और इसकी एक्सपेक्टेड डेट आफ कम्पलीशन 1992 है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पुल की जो योजना है, क्या वह दो पार्टस में है यानी मेरा आशय यह है कि इस पुल में एक रास्ता आने के लिए और दूसरा जाने के लिए होगा ? क्या इस प्रकार की कोई योजना है ?

श्री राजेश पायलट : चेयरमैन साहब, नक्शे में तो यह एक बाई-पास है और बनारस शहर और रामनगर, दोनों का बाई-पास से नदी पर पुल बनेगा ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह पुल जो वाराणसी, रामनगर और मुगलसराय को जोड़ने के लिए बन रहा है इसके निर्माण का